Newspaper Clips
October 12-13, 2016

October 13

Business Line ND 13.10.2016 P-13

Move for research tie-up with global institutions

IIT-NIT alumni networks to facilitate collaborations with foreign entities

OUR BUREAU

Chennai, October 12

The Union HRD Ministry is tapping the alumni networks of IITs and NITs to enable collaboration between leading technological institutions and their counterparts globally for cutting-edge research.

The Ministry has chosen IIT Alumni Centre, Chennai, to drive an all-India initiative called Touchstone, which will act as a catalyst to link Centrally-funded technological universities and global institutions.

Connector and catalyst

Touchstone will be a service offered to Indian academia by alumni fraternity and play the role of 'connector and catalyst' facilitating cross-border research alliances, said S Gopal, president, IITAC, at the launch.

Lakshmi Narayanan, vice-chairman, Cognizant Technology Solutions, and part of Touchstone Advisor Board, said the Centre would provide sufficient funds, running into hundreds of crores, to Touchstone.

IITAC initiative

This all-India initiative was launched in Chennai because IITAC took the initiative, he told newspersons on the sidelines of the launch.

Volunteers mobilised by IITAC will work on enabling collaborations in 79 institutions such as IITs, NITs, IIITs and IISERs across 20 research verticals.

It could be for joint research projects, exchange of research fellows, and joint guidance for Ph D scholars to attract promising young overseas faculty to research and teach in India, Gopal said.

R Gopalakrishnan, CEO, Mindworks, and former director of Tata Sons; Arjun Malhotra, chairman, Evolko Inc, Magic Software Inc & Mapmygenome India; Lakshmi Narayanan of Cognizant; and MS Ananth, former Director, IIT-Madras, will form Touchstone Advisory Board, Gopal said.

Volunteer champions

Touchstone will have 25 volunteer champions, all business leaders of stature. They would spare four to eight hours a week for the cause.

Gopalakrishnan, leader of the advisory board of Touchstone, while launching the initiative, said, "This is a laboratory, a prototype we are trying to make, and a significant experiment."

Navodaya Times ND 13.10.2016 P-2

आईआईटी, एनआईटी सहित देश के करीब 600 विवि. को मिलेगी सुविधा

केंद्र के सभी उच्च शिक्षा संस्थान होंगे वाईफाई

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (बृजेश सिंह) केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देश के सभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, प्लानिंग स्कूल्स तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पूरे परिसर को वाई-फाई से लैस कराने का फैसला लिया है। इस फैसले पर तत्काल अमल शुरु करने के लिए मंत्रालय कीओर से टेंडर भी आमंत्रित किये जा चुके हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में अकादमिक भवन के अलावा, हास्टल, लाइब्रेरी, कैंटीन तथा अन्य सभी ऐसी जगहें जहां छात्र प्राय: उपस्थित रहते हैं वाई-फाई से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाऐगा। उल्लेखनीय है कि देश के लगभग 600 विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) से जोड़ने के लिए पूरी तरह वाईफाई करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इसमें से ज्यादा तर संस्थान व विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं। केंद्र सरकार सीधे देश में 30 एनआईटी, 20आईआईटी, सात आईआईएसईआर, तीन स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड स्ट्रक्चर (एसपीए) तथा 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का संचालन करता है। राज्य संचालित शिक्षा संस्थान व विश्वविद्यालयों में वाईफाई लगवाने का जिम्मा राज्य सरकारों को दिया गया है जबकि केंद्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में सीधे मानव संसाधन मंत्रालय वाई फाई लगवा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में वाईफाई लगवाने के लिए सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाडर से बात की जा रही है।

छात्रों को मिलेगी फुल स्पीड व अनलिमिटेड डेटा

सर्विस प्रोवाइडर को विश्वविद्यालय कुल छात्रों की कुल संख्या के हिसाब से हर महीने इंटरनेट फीस का भुगतान करेगी। सर्विस प्रोवाइडर को छात्रों की संख्या को देखते हुए वाई-फाई लगाने के लिए मानक भी तय कर दिये गये हैं। छात्रों को मोबाइल तक कम्प्यूटर व लैपटाप पर सीधे यह कनेक्शन उपलब्ध होगा।

Rashtriya Sahara ND 13.10.2016 P-5

आईआईटी खड़गपुर 20 से 22 जनवरी तक राजधानी में आयोजित करेगा फेस्ट

नई दिल्ली । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर का राजधानी के शाहदरा स्थित क्रॉस रीवर मॉल में अपना वार्षिक व सामाजिक उत्सव स्प्रिंग फेस्ट आयोजित करेगा। एशिया में सबसे बड़े उत्सव में से एक स्प्रिंग फेस्ट पूरी तरह से विद्यार्थियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस फेस्ट में देशभर से 25 हजार से ज्यादा लोग अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। यह तीन दिनों तक चलेगा। उत्सव 20 से 22 जनवरी 2017 तक चलेगा। इस साल स्प्रिंग फेस्ट से पूर्व अपने नेशनवाइड प्रीलिम्स के प्रमुख चार कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक, एकल नृत्य, समूह नृत्य व एसएफ आइडल अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के अलावा इसका आयोजन छह शहरों चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, पुणे, हैदराबाद व बेंगलुरु में भी होगा।■ **एसएनबी**

IIT-M launches online counselling

http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/IIT-M-launches-online-counselling/articleshow/54819902.cms

CHENNAI: To help students easily access mechanisms that can assist in dealing with stress, Indian Institute of Technology, Madras has introduced an online emotional wellness platform called 'YourDOST aims to increase awareness regarding mental wellness and break the prevalent social stigma attached to seeking psychological help on campus. The mechanism has been introduced in the hope that a larger number of students would be more comfortable on an online forum when compared to the existing face-to-face system.

The anonymous forum functions similar to a chatroom where students with a user ID and password can log onto a counselling session. These sessions are usually a one-on-one with a professional at the other end. The institute has roped in a number of experts including psychologists, life coaches and career coaches.

General secretary of the student body, Purab Jain says that there is a lot of stigma attached to counselling. "Many aren't comfortable saying they are taking up a counselling session. We already had a regular counselling mechanism where counsellors come to the campus. However, some students may feel uneasy about going to a counsellor's room with other students watching. This is precisely why YourDOST was launched," he said.

On the other hand, the institute is also strengthening its peer support network. The guidance and counselling team IIT-M called 'Mitr' has now been split into two wings -proactive guidance and reactive guidance. 'Saathi' the proactive wing of the campus involves around 250 student mentors involved in creating awareness and sensitizing students about overall well-being. It will also manage platforms to support enhancement of skills for personal and professional growth.

"Each of the 250 mentors have about 5 mentees, most of the mentees being first-year students as they are new to campus. Mentors will help resolve issues at the student level or suggest professional help if required," said Jain, adding that another level of mentors will cater to the seniors. Mitr which remains the other wing now deals with reactive mechanism where students help others deal with the aftermath of an issue or an incident or could also involve disciplinary action, said the student body.

October 12

Business Standard ND 12.10.2016 P-9

आईआईटी-दिल्ली की नजर विदेशी छात्रों पर

साहिल मक्कड़

आईआईटी दिल्ली क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 6 स्थान गिरकर 185वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि संस्थान ने अकादमिक साख के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि साइटेशन पर फैकल्टी के मामले में यह नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) से भी आगे है। साथ व्यक्तिगत स्तर पर संस्थान के कई विभाग शीर्ष 100 में शामिल हैं लेकिन उसे विदेशी छात्रों और शिक्षकों की कमी का खमियाजा उठाना पड़ा है। यह रैंकिंग मुख्यत: छह सूचकांकों अकादमिक साख, नियोक्ता साख, छात्र-शिक्षक अनुपात, साइटेशन पर फैकल्टी, विदेशी शिक्षक और छात्र अनुपात। आईआईटी दिल्ली के उप निदेशक एम बालकृष्णन स्वीकार करते हैं कि विदेशी छात्रों, शिक्षकों और परिसर में जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण संस्थान की रैंकिंग में गिरावट आई है। उन्होंने कहा, 'रैंकिंग में करीब 40 फीसदी बरीयता संस्थान की छवि, इसके परिसर और बुनियादी सुविधाओं को दी गई है।'

आईआईटी-दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी और तबसे संस्थान का कोई व्यापक विस्तार नहीं हुआ है। एनयूएस जैसे एशिया के अत्याधुनिक विश्वविद्यालयों के आगे यह कहीं भी नहीं ठहरता है। एनयूएस की स्थापना 1980 में हुई थी और क्यूएस रैंकिंग में यह दुनिया में 12वें और एशिया में पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग में एशिया में 35

विश्वविद्यालय आईआईटी-दिल्ली से आगे हैं। धारणा से ज्यादा विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों और शिक्षकों की संख्या और अकादमिक साख के आधार पर आंका जाता है। संस्थान का मानना है कि रैंकिंग में खराब प्रदर्शन का एक कारण यह भी है कि यहां विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम नहीं है। यहां अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की तरह व्यवस्था नहीं है जहां विदेशी छात्रों को शोध के लिए फंड दिया जाता है। इस समय दिल्ली में 80 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं जिन्हें उनके देश की सरकारें या बाहरी संस्थाएं मदद कर रही हैं। बालकृणन कहते हैं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए संस्थान मानव विकास मंत्रालय को सलाह देगा कि वह विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करे। मंत्रालय ने सभी आईआईटी संस्थानों की विश्व रैंकिंग सुधारने के लिए पिछले महीने विश्वजीत नाम से एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है।

बालकृणन ने कहा कि अगले साल से सरकार विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया सहित कई देशों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी। सरकार का मानना है कि इन देशों में आईआईटी और इसके पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में दो-तीन साल लगेंगे।

सभी आईआईटी विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए हरसंभव उपाय कर रहे हैं लेकिन विदेशी शिक्षकों के मामले में उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये संस्थान विदेशी शिक्षकों को ऊंचा वेतन देने में सक्षम नहीं हैं।

संख्या गणित

2,300	पीएचडी शोध/छात्र
480	शिक्षक
4	विदेशी शिक्षक
8,200	छात्र
1:18	शिक्षक- छात्र अनुपात
80	विदेशी छात्र

साथ ही उनके ठहरने की व्यवस्था और प्रयोगशाला जरूरतों को पूरा करना भी आसान नहीं है।

आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर ने नाम न आने की शर्त पर कहा, 'जब आईआईटी खाली पड़े पदों पर भारतीय शिक्षकों की ही भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वे ऊंची तनख्वाह वाले विदेशी शिक्षकों की सेवाएं कैसे ले सकते हैं। विदेशी शिक्षक विकासशील देशों के बजाय विकसित देशों को पसंद करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं।'

शिक्षकों की भर्ती की मौजूदा व्यवस्था बहुत धीमी है और प्रोफेसरों के सेवानिवृत्त होने से यह समस्या और विकराल हो गई है। कुछ खबरों के मुताबिक सभी आईआईटी संस्थानों में शिक्षकों के 2,600 पद खाली हैं। आईआईटी दिल्ली में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:18 है लेकिन फिर भी संस्थान में 300 और शिक्षकों की जरूरत है। 2008-09 और 2010-11 के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा लागू किए जाने के बाद से आईआईटी में शिक्षक-छात्र अनुपात बिगड़ गया है। फिलहाल 23 आईआईटी संस्थानों में 72,000 छात्र पढ़ रहे हैं। 2020 में इन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इसे देखते हुए आईआईटी-दिल्ली और दूसरे संस्थानों में देसी-विदेशी शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही पीएचडी धारकों के जरिये भी शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। आने वाले दिनों में पुराने आईआईटी संस्थान दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर और बंबई पीएचडी स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। हालांकि सरकार ने पीएचडी धारकों को आईआईटी संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति देकर इस समस्या का अल्पकालिक हल निकाल लिया है लेकिन इन संस्थानों को विश्व रैंकिंग में ऊपर पहुंचाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के मद में ज्यादा फंड देने की जरूरत है।

Punjab Kesari 12.10.2016 P-5

आईआईटी के लिए 15 अक्तूबर को होगा प्रीलिम्स प्रोग्राम

पश्चिमी दिल्ली, (ब्यूरो): आईआईटी खड़गपुर में होने वाले वार्षिक स्प्रिंग फेस्ट के लिए दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में 15 अक्तूबर को प्रीलिम्स प्रोग्राम होगा। कार्यक्रम में छात्र प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली के कई कॉलेजों के छात्र हिस्सा लेंगे। वार्षिक स्प्रिंग फेस्ट के लिए इस वक्त देशभर में नुक्कड़ नाटक, एकल नृत्य और समूह नृत्य के माध्यम से प्रतिभाओं की खोज की जा रही है। फेस्ट में जीतने वाली टीम को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है।

Amar Ujala ND 12.10.2016 P-6

पहली बार वेबसाइट पर दस साल के पेपर

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर।

आईआईटी में एडमिशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस 2017 के पिछले 10 साल (2007 से 2016 तक) के पेपर पहली बार वेबसाइट jeeadv.ac.in पर उपलब्ध करा दिए गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखकर पेपर के सही पैटर्न का आकलन किया जा सकता है। इसकी मदद से कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारी आसान बनाई जा सकती है।

जेईई एडवांस 2017 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार की प्रवेश परीक्षा आईआईटी मद्रास की देखरेख में होगी। 21 मई 2017 को दो

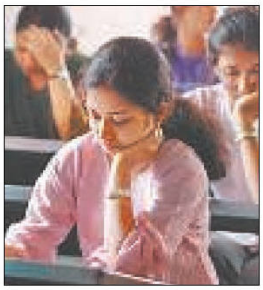

पालियों (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम पांच बजे तक) में परीक्षा कराई जाएगी।

आईआईटी मद्रास की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले शैक्षिक सत्र (2016-17) में दो लाख 20 हजार स्टूडेंट जेईई एडवांस का पेपर देंगे। पिछले सत्र (2015-16) में दो लाख स्टूडेंटों ने पेपर दिया था। सभी कोर्स की 15 फीसदी सीटें एससी और सात फीसदी एसटी के लिए आरक्षित रहेंगी।

विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए आईआईटी का फैसला

छात्रों की संख्या तय

आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तय कर दी गई है। सामान्य श्रेणी (ओपेन कैटेगरी) के 1,11,100 स्टूडेंट पेपर दे सकेंगे। ओबीसी के 59,400, एससी के 33 हजार और एसटी के 16, 500 स्टूडेंटों को पेपर देने का मौका मिलेगा।

Hindustan ND 12.10.2016 P-5

आईआईटी- आईआईसी परीक्षा 12 फरवरी को होगी

कार्यक्रम

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईसी) के एमएससी, ज्वाइंट एमएससी-पीएचडी, एमएससी-एमटेक और अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जैम-2017) का 12 फरवरी को आयोजन किया जायेगा।

इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार के ई-मेल पर ई-मेल आएगा, जिसमें पंजीकरण नंबर होगा। इसके बाद उम्मीदवार पोर्टल पर लॉगइन करके अभिभावकों का नाम, मोबाइल नंबर, परीक्षा केंद्र के लिए शहर का चुनाव, जन्मतिथि, पत्र व्यवहार के लिए पता, श्रेणी आदि की जानकारी देंगे।

तैयारी

- दो पालियों में आयोजित की जाएगी जैम-2017 परीक्षा
- दोनों ही सत्र में परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी

दो सत्र में परीक्षा होगी : परीक्षा दो सत्रों में होगी। पहले सत्र में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच बायोलॉजिकल साइंस, गणित और भौतिकी के पेपर होंगे। दोपहर 2 शाम 5 बजे के बीच बायोटेक्नोलॉजी, रसायन शास्त्र, जियोलॉजी व मैथमेटिकल स्टैटिसटिक्स की परीक्षा होगी।

Business Standard ND 12.10.2016 P-9

कैसे सुधरेगी उच्च शिक्षण संस्थानों की विश्व रैंकिंग

एम सरस्वती

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के मामले में आईआईटी-बंबई अपने साथी संस्थानों की तुलना में काफी आगे हैं। लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में आगे बने रहने के लिए यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि क्यूएस की 2016-17 की विश्व रैंकिंग में यह 219वें स्थान पर फिसल गया है। पिछले साल संस्थान की रैंकिंग 202 थी।

आईआईटी-बी में 23 विदेशी शिक्षक और 65 विदेशी छात्र हैं। संस्थान ने 25 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ करार किया है और वर्ष 2014-15 में यहां के छात्रों और शिक्षकों के 1,430 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अलबत्ता स्तरीय विदेशी संस्थानों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। क्यूएस की रैंकिंग में आईआईटी-बी को अकादमिक साख के 54.7 अंक मिले जो आईआईटी दिल्ली (47.2) और आईआईटी मद्रास (41.1) से ज्यादा है। लेकिन यह 12वीं रैंकिंग की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से बहुत कम है जिसे पूरे 100 अंक मिले हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के मामले में साख की बहुत अहमियत होती है क्योंकि इसी से विदेशी शिक्षक और छात्र आकर्षित होते हैं। परिसर में विविधता को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ऊंची साख का प्रत्यक्ष परिणाम माना जाता है बल्कि इससे विचार, अनुभव और संस्कृति के आदानप्रदान से छात्रों के रोजगार पाने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी विविधिता के इर्दगिर्द आईआईटी-बी ने अपनी रैंकिंग और साख में सुधार की योजना बनाई है।

आईआईटी-बी के निदेशक देवांग खोखर कहते हैं, 'हम शिक्षा और शोध के स्तर को सुधारने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हमारा ध्यान रैंकिंग पर नहीं है लेकिन इन उपायों से रैंकिंग में सुधार होगा।' उनका कहना है कि क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी-बी की रैंकिंग इसलिए गिरी है क्योंकि दूसरे संस्थानों की रैंकिंग तेजी से सुधरी है। संस्थान के एक अन्य प्रोफेसर ने कहा कि दूसरे संस्थानों ने शोध के मामले में काफी सुधार किया है। उन्होंने कहा, 'हमारे यहां हर साल डॉक्टर की डिग्री पाने वालों की संख्या बढ़ रही है लेकिन दूसरे संस्थानों में इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।'

आईआईटी-बी की 2014-15 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि संस्थान अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के साथ अपने संस्थानों को बहुत अहमियत दे रहा है।

पवई में 200 हेक्टेयर में फैला आईआईटी-बी का परिसर विहार, पोवई झील और हरी-भरी पहाड़ियो से घिरा है जो इसे नियोक्ताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के लिए पसंदीदा जगह बनाता है। संस्थान के विदेशी संबंधों की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। आईआईटी-बी की स्थापना 1958 में हुई थी और यह विदेशी सहयोग से बनने वाला देश का पहला संस्थान था। पूर्व सोवियत संघ ने यूनेस्को के जरिए इसके लिए धन की व्यवस्था की। संसद ने 1961 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया।

आईआईटी-बी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा विदेशी शिक्षकों को यहां लाने की कोशिश में जुटे हैं।'

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के साथ-साथ संस्थान शोध का स्तर बढ़ाने पर भी जोर देगा। इस साल संस्थान ने 325 पीएचडी डिग्रियां दीं। यह संख्या पिछले साल 230 और उससे पिछले साल 227 थी। वर्ष 2015-16 में भारतीय पेटेंट के लिए 128 आवेदन किए गए। पिछले साल यह संख्या 72 और वर्ष 2013-14 में 61 थी। आईआईटी-बी की योजना शोध के लिए फंड बढ़ाने की भी है। संस्थान में 15 विभाग, 17 केंद्र और चार अंतरविषयक कार्यक्रम हैं। उसे साल 2015-16 में सरकार की तरफ से कुल 515.06 करोड़ रुपये का अनुदान मिला जिसमें से 255.07 करोड़ रुपये शोध एवं विकास के लिए थे। संस्थान की 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में आईआईटी-बी को शोध एवं विकास के लिए मिलने वाली राशि में सालाना 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2015 में यह राशि 243 करोड़ रुपये थी। इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन कई दूसरे क्षेत्रों में उसे समस्याओं से पार पाना होगा। वर्ष 2014-15 में संस्थान ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ 25 करारों पर हस्ताक्षर किए और सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए दुनियाभर के सरकारी प्रतिनिधिमंडलों की अगवानी की।

इस तरह की शोध गतिविधियों और सहयोग का नतीजा यह हुआ कि आज संस्थान में शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या है। फिलहाल आईआईटी-बी में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:16 है। संस्थान में पिछले साल 155 शिक्षक थे और यहां से 2,515 छात्रों ने स्नातक की डिग्री ली। संस्थान लिंग विविधता जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दे रहा है। आईआईटी-बी के प्रवक्ता के मुताबिक संस्थान में मास्टर्स और पीएचडी में पुरुष-महिला अनुपात बढ़ रहा है। स्नातक स्तर पर अनुपात घटता बढ़ता रहता है लेकिन फिर भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है। संस्थानों की रैंकिंग उनमें उपलब्ध सुविधाओं पर भी निर्भर करती है। क्यूएस इंटेलीजेंस यूनिट में शोध विभाग के प्रमुख बेन साउटर रैंकिंग में भारतीय संस्थानों के खराब प्रदर्शन का कारण पीएचडी डिग्रीधारी शोधार्थियों और विदेशी शिक्षकों की संख्या में कमी को मानते हैं। आधुनिक और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्य संस्कृति का शोध और प्रशिक्षण पर गहरा असर पड़ता है।

संख्या गणित

- 325 – पीएचडी डिग्रियां दी गईं
- 65 – विदेशी छात्र
- 23 – विदेशी शिक्षक
- 1:16 – शिक्षक-छात्र अनुपात
- 255.07 – करोड़ रुपये शोध एवं विकास के लिए

Rajasthan Patrika ND 12.10.2016

देश में बनेंगे विश्वस्तरीय संस्थान ताकि टॉप 200 में शामिल हों हम

एचआरडी मंत्रालय ने 28 तक मांगे संस्थाओं से सुझाव

रक्तिम तिवारी
rajasthanpatrika.com

अजमेर . कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर भारत में भी विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंड पूरा करने वाले मौजूदा संस्थानों को विश्व स्तरीय संस्थानों का दर्जा दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व स्तरीय संस्थान अधिनियम-2016 तैयार कर लिया है। मंत्रालय ने 28 अक्टूबर तक संस्थाओं से अधिनियम पर सुझाव मांगे है।

देश में पिछले 69 साल में आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विवि, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे नामचीन संस्थान स्थापित हुए है। इनमें से कोई संस्थान टॉप-200 की विश्व स्तरीय श्रेणी में शामिल नहीं है। इस पर राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी भी चिंता चुके है। विश्वविद्यालय संघ की वेस्ट जोन कुलपति कॉन्फ्रेंस में भी यह मुद्दा उठा। लिहाजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व स्तरीय संस्थान अधिनियम-2016 तैयार कर लिया है।

ये सुविधाएं

समूचे संस्थान में वाई-फाई सुविधा

अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं

दुनिया के नामचीन संस्थानों से सीधा संपर्क

विभिन्न पाठ्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश

सामान्य पढ़ाई के अलावा रिसर्च पर सर्वाधिक जोर

विद्यार्थियों का टॉप संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट

देश उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थान

784 राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी-
47 केंद्रीय विश्वविद्यालय
45 हजार कॉलेज
23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
20 भारतीय प्रबंधन संस्थान-
22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-
5.3 करोड़ अध्ययनरत विद्यार्थी
(स्रोत-यूजीसी)

एचआरडी मंत्री के पास भेजा जाएगा

विश्व स्तरीय संस्थानों के लिए बनाए गए अधिनियम पर 28 अक्टूबर तक संस्थाएं ई-मेल और हार्ड कॉपी भेजकर सुझाव और टिप्पणी दे सकेंगी। इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भेजा जाएगा।

प्रो. जसपाल सिंह संधु,
सचिव यूजीसी

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दो संस्थाएं

गौरतलब है कि में मुम्बई आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को टाइम्स हायर एज्यूकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप-100 में जगह दी गई है। इससे पहले किसी भी सरकारी अथवा निजी भारतीय संस्थान को टॉप-100 में स्थान नहीं मिल सका है। वहीं इस मामले में चीन, अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के यूनिवर्सिटी अग्रणीय है।

बनेंगे नए संस्थान, पुरानों को मिलेगा दर्जा

विद्यार्थियों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए देश में विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे। इसके अलावा देश में मौजूदा आईआईटी, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम), केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को विश्व स्तरीय संस्थानों का दर्जा मिलेगा। इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिनियम की शर्तें पूरी करने पर ही यह दर्जा दिया जाएगा। संस्थानों में कमियों पर रहने पर उन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा।

Business Standard ND 12.10.2016 P-9

उतार-चढ़ाव के बीच आईआईटी कानपुर

वीरेंद्र सिंह रावत

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (आईआईटी-के) के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना उतना ही उतारचढ़ाव भरा रहा जितना लखनऊ से ग्रैंड ट्रंक सड़क के जरिये 100 किलोमीटर दूर इसके परिसर तक पहुंचना।

कानपुर हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा है, सड़कों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है लेकिन फिर भी 1,055 एकड़ में फैले आईआईटी के शानदार परिसर में पहुंचने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों (ज्यादातर घरेलू) का तांता लगा रहता है। संस्थान स्वीकार करता है कि वह हाल तक अपनी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग को लेकर संतुष्ट था।

लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यूएस की हालिया वर्ल्ड रैंकिंग्स में आईआईटी कानपुर 271वें स्थान से फिसलकर 302वें स्थान पर पहुंच गया है। संस्थान अपना खोया स्थान वापस लेना चाहता है। इसके लिए उसने कई स्तरों पर प्रयास करने की योजना बनाई है। इसके लिए रैंकिंग एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल और परिसर में छात्रों और शिक्षकों के जरिये शोध को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

आईआईटी कानपुर ने रैंकिंग संस्थाओं के साथ बेहतर तालमेल और उन्हें आंकड़े मुहैया कराने के लिए एक ग्लोबल रैंकिंग कमेटी बनाई है। संस्थान ने कई ऐसे मानकों की पहचान की है जिन पर काम करने की जरूरत है। इनमें शिक्षक और छात्र अनुपात, अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों की संख्या, शोध पत्रों की संख्या तथा परिसर में शोध छात्रों की संख्या शामिल है।

संस्थान के उप निदेशक ए के चतुर्वेदी ने स्वीकार किया कि शिक्षकों और छात्रों के बीच अनुपात तथा शोध छात्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में संस्थान की रैंकिंग पर असर पड़ा है। उन्होंने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'पिछले 4-5 साल में परिसर में छात्रों की संख्या करीब 2000 यानी करीब 25 फीसदी बढ़ी है लेकिन इस दौरान शिक्षकों की संख्या 10-15 प्रतिशत ही बढ़ी है।' संस्थान में शिक्षकों के मंजूर पदों की संख्या करीब 650 है लेकिन यहां 6,400 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल 400 है। यानी 16 छात्रों पर एक शिक्षक। संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ शिक्षकों के मुताबिक यह शिक्षकों और छात्रों के बीच 1:10 का अनुपात होना चाहिए।

रैंकिंग में सुधार और पहचान बढ़ाने के लिए संस्थान का जोर शोध पर रहेगा। चतुर्वेदी का कहना है कि आईआईटी कानपुर की विश्व रैंकिंग में गिरावट का एक कारण यह है कि दूसरे आईआईटी की तुलना में यहां पीएचडी के छात्रों की संख्या कम है। उन्होंने कहा, 'पीएचडी के छात्रों की संख्या में कमी के पीछे ऐतिहासिक कारण हैं क्योंकि संस्थान ने संख्या के बजाय गुणवत्ता को अहमियत दी है। लेकिन अब हमारे पास छात्रों की संख्या बढ़ी है और ज्यादा छात्र पीएचडी कर रहे हैं।'

आईआईटी कानपुर ने पिछले साल पीएचडी की 150 डिग्रियां बांटी थी और इस साल इसके 175 पहुंचने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में इस संख्या के धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। हालांकि संस्थान ने शिक्षकों के शोध पत्रों की स्थिति और योजना के बारे में जानकारी नहीं दी लेकिन संस्थान के एक सूत्र ने कहा कि इस संख्या में सुधार आ रहा है। शिक्षकों को बेहतर शोध कार्य करने को कहा गया है ताकि शिक्षा जगत में संस्थान की छवि बेहतर बनाई जा सके।

संख्या गणित

175 पीएचडी शोधार्थी	6,400 छात्र
400 शिक्षक	1:16 शिक्षक छात्र अनुपात
10 विदेशी शिक्षक	₹500 cr करोड़ रुपये शोध के लिए

स्रोत - संस्थान

आईआईटी कानपुर से पेटेंट के लिए 350 आवेदन किए गए। इनमें से 41 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट और 10 डिजाइन के लिए हैं। इनमें से अब तक 34 पेटेंट प्रदान किए जा चुके हैं और 53 को व्यवसायीकरण के लिए तकनीकी लाइसेंस मिल चुका है। अनुसंधान एवं विकास के लिए धन की कमी चिंता का विषय है। यह राशि करीब 500 करोड़ रुपये है जिसमें 100 करोड़ रुपये की प्रायोजित परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश फंड केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा आवंटित किया जाता है। सरकार बजट में 450 करोड़ रुपये संस्थान के लिए आवंटित करती है। साथ ही उसे विभिन्न प्रयोजनों, परीक्षाएं आयोजित कराने, शोध एवं विकास तथा छात्रावास फीस के तौर पर 200 करोड़ रुपये मिले हैं। लेकिन वार्षिक कोष में से 60 फीसदी तो वेतन और दूसरे प्रशासनिक खर्चों में निपट जाता है।

आईआईटी कानपुर ने फंड की कमी को पूरा करने के लिए प्रायोजित परियोजनाओं को लेना शुरू कर दिया है। साथ ही संस्थान में पढ़ाई कर चुके छात्रों से भी मदद ली जा रही है। फंड और सहयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा उद्योगों का सहारा लिया जा रहा है। संस्थान ने हाल में ये कदम उठाए हैं और उसे भरोसा है कि आने वाले वर्षों में उसे इसका लाभ मिलेगा। चतुर्वेदी ने कहा कि लक्ष्यों को पाने के लिए समयसीमा निर्धारित हैं।

Business Standard ND 12.10.2016 P-9

निजी शोध फंडिंग आईआईएससी के लिए मददगार

अपूर्वा वेंकट

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के छात्रों को दुनिया की कंपनियां हाथोंहाथ लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्थान का जोर शोध, मूल विज्ञान और इंजीनियरिंग पर रहता है। यह संस्थान एशिया के शीर्ष संस्थानों में शामिल है लेकिन उसे अपनी स्थिति सुधारने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016-17 में आईआईएससी 147वें से 152वें स्थान पर फिसल गया है। वैश्विक रैंकिंग के मामले में संस्थान ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। आईआईएससी के मृदुभाषी निदेशक अनुराग कुमार ने स्वीकार किया कि बेहतर पारदर्शिता के लिए हाल के वर्षों में संस्थान ने रैंकिंग संस्थानों को आंकड़े देने की प्रक्रिया शुरू की है।

कुमार ने संस्थान के पूर्व छात्रों से कहा था, 'हम रैंकिंग संस्थाओं को पूरे आंकड़े नहीं दे रहे थे। कुछ महीने पहले हमने एक समिति बनाई है और एक सलाहकार की नियुक्ति की है जो इन संस्थाओं को जरूरी आंकड़े मुहैया कराएगा।'

आईआईएससी के पक्ष में जो एक बात जाती है वह यह है कि निजी क्षेत्र ने ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए संस्थान में निवेश करने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। संस्थान को हर साल सरकार से औसतन 350 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसके अलावा प्रायोजित शोध के जरिये 220 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं।

संख्या गणित

2,200	पीएचडी छात्रों की संख्या
25	विदेशी छात्र
23	विदेशी शिक्षक
7:1	छात्र:शिक्षक अनुपात
570	करोड़ रुपये शोध एवं अनुसंधान के लिए फंड

प्रायोजित शोध को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे आईआईएससी के पूर्व छात्रों का कहना है कि न केवल सरकार से बल्कि निजी क्षेत्र से भी अच्छा खासा निवेश आ रहा है। निजी क्षेत्र तब तक निवेश नहीं करेगा जब तक उसे यह यकीन न हो जाए कि यह विश्व स्तरीय संस्थान है। निजी क्षेत्र इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपये देता है। संस्थान रैंकिंग संस्थानों को पूरे आंकड़े देने के काम में जुटा है लेकिन साथ ही वह वैश्विक रैंकिंग में ज्यादा पारदर्शिता चाहता है। इंजीनियरिंग विभाग के डीन एम के सुरप्पा का मानना है कि रैंकिंग संस्थाओं को रैंकिंग के मामले मं पर्याप्त सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषकर शोध के तरीके के बारे में ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है।

सुरप्पा का कहना है कि रैंकिंग संस्थानों के कई मानक किसी संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता को परिलक्षित नहीं करते हैं। किसी संस्थान के शिक्षकों के उद्धरण की संख्या भी इनमें एक है। उन्होंने कहा, 'शोध पत्रों की संख्या नहीं बल्कि उनके असर को पैमाना बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।' उनका कहना था कि न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बल्कि सुविधाओं की उपलब्धता से भी शोध कार्य प्रभावित होता है। संस्थानों का कामकाज और प्रक्रियाएं शोध कार्यों को बढ़ावा देने के अनुकूल नहीं हैं जिससे उनकी रैंकिंग प्रभावित होती है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तरह आईआईएससी को भी अगर रैंकिंग में ऊपर जाना है तो उसे अपने परिसरों में विदेशी छात्रों की संख्या को बढ़ाना होगा। संस्थान में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:7 है जो आईआईटी की तुलना में बहुत अच्छा है। साथ ही यहां पीएचडी छात्रों की भी अच्छी खासी संख्या है। आईआईएससी में करीब 4,000 छात्र हैं लेकिन विदेशी छात्रों की संख्या महज एक फीसदी के आसपास है। साथ ही संस्थान को महिला छात्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों का अनुपात 5:1 है। आईआईएससी के 420 शिक्षक बेंगलूरु और चल्लाकेरे परिसरों में बराबर बंटे हुए हैं। बेंगलूरु से 220 किमी दूर स्थित चल्लाकेरे परिसर 2000 एकड़ में फैला है। आईआईएससी की विस्तार योजना के तहत इसे पिछले दशक के अंत में स्थापित किया गया था।

संस्थान में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चल्लाकेरे परिसर में एक सिन्क्रोट्रोन स्थापित किया जा रहा है जो बड़ा और उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन एक्सिलिरेटर है। हालांकि सुरप्पा का कहना है कि भारतीय संस्थानों को ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि शोध का वैश्विक असर देखने को मिले। उन्होंने कहा, 'यहां कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होने से शोध पत्रों और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।'

Virat Vaibhav ND 12.10.2016 P-15

टैक्सी के बाद अब ट्रक-टेम्पो ट्रांसपोर्टरों को संगठित करने का ऐप

एजेंसी ■ नई दिल्ली

इंजीनियरिंग स्नातक तीन युवा उद्यमियों द्वारा शहरों के अंदर छोटे वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन करने वाले असंगठित परिचालकों को ओला और उबर जैसे ऐप आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर संगठित करने के लिए शुरू किए गए उद्यम 'पोर्टर' में इस समय बेंगलुरू और दिल्ली सहित पांच शहरों में 3,000 से अधिक हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) जुड़ चुके हैं।

पोर्टर ने निकट भविष्य में अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े एलसीवी की संख्या 50,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने वाले युवा उद्यमी एवं बेंगलुरू से शुरू इस स्टार्टअप 'पोर्टर' के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणव गोयल ने 'भाषा' से कहा कि पोर्टर का उद्देश्य छोटे वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन करने वालों, खासकर अपने टेम्पो-ट्रक खुद चलाने वाले लोगों को एक मंच पर संगठित कर उनका कारोबार बढ़ाने में मदद करना है।

गोयल ने कहा कि दो साल पहले देश की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) राजधानी बेंगलुरू से शुरू किए गए इस उद्यम में बेंगलुरू, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में 3,000 से अधिक एलसीवी ऑपरेटर जुड़ चुके हैं। 'हमारा लक्ष्य इस संख्या को निकट भविष्य में 50,000 तक पहुंचाना है।'

उन्होंने कहा, 'पोर्टर उन्हें एक ऑनलाइन मंच मुहैया कराता है जहां ग्राहक और वाहन मालिक आपस में एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। वाहनों में जीपीएस प्रणाली लगे होने से ग्राहक को उनकी वास्तविक स्थिति का पता चलता रहता है। इसी तरह कोई वाहन किसी स्थान पर सामान की आपूर्ति करने गया है तो लौटते समय उसे उस स्थान से ढुलाई का ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती है।'

IIT-D alumna develops app to monitor pollution levels

http://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/IIT-D-alumna-develops-app-to-monitor-pollution-levels/articleshow/54787032.cms

GURGAON: Namita Gupta, an IIT-Delhi alumna, moved to Gurgaon from the US in the winter of 2014 — the same year when Delhi hogged international headlines for being the world's most polluted city.

Hardly did she expect a winter that she would survive on antibiotics. What bothered her even more was the discomfort of her daughter who is an asthma patient.

Gupta first thought of going back to the US, but decided against it. Instead, she developed an application to help monitor air pollution levels. The app, Airveda, is quite simple to operate — one can download it from Google Play and select the applicable region, and the app will read from the nearest pollution monitoring station and display it.

"We keep reading about pollution levels, but we never know the actual level air pollution levels. Airveda lets us track the levels and plan our activities better depending on the indoor and outdoor pollution levels," said Gupta, who had previously worked with Zomato as chief product officer.

Gupta, who had also worked for 12 years at Facebook and Microsoft, vouches for the use of monitoring herself. "My daughter has asthma and she was miserable the winter before last. We could bring down her discomfort considerably last winter with constant monitoring of air pollution levels," she said.

She added, "Knowing the air quality levels let us decide whether to send my daughter out to play or whether she needs a mask while going to the school in the morning. Beyond monitoring the air quality, the app also lets one find out if their air purifiers are working efficiently or not."

The application also offers a notification feature that alerts you if the air quality levels are too bad and if the filters of the air purifiers have stopped working.

Realising that there aren't enough monitoring stations, Gupta is also working on installing air monitors across different cities and has one installed outside her residence on Golf Course Road.